Vol 5 Issue 10 July 2016

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.1402(UIF) Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

Review Of Research

भारतीय प्रशासन तंत्र में नवाचार एवं ई–प्रशासन के बढ़ते आयाम

डॉ. श्रद्धा गर्ग
अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, सागर (म.प्र.)

सारांश–
ई–गवर्नेंस वर्तमान समय की एक नई अवधारणा के रूप में गुंजायमान हुई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरूचि के साथ ही प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। ई–प्रशासन जनआकांक्षाओं के राष्ट्रीय आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्षम विकास और प्रभावपूर्ण प्रशासन पद्धतियों के विकास के लिए आवश्यक है इसलिए प्रशासन में ई–प्रषासन का उपयोग अधिक से होना चाहिए। उपर्युक्त पृश्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय प्रशासन तंत्र में नवाचार एवं ई–प्रशासन के बढ़ते आयाम पर केन्द्रित है।

संकेतकः प्रस्तावना, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ई–शासन ऑनलाइन सेवा, निष्कर्ष।

प्रस्तावना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विगत वर्षों में युगांतकारी परिवर्तन आए हैं। वर्तमान दौर सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति का समय है सूचना के क्षेत्र में इस क्रांति का सूत्रपात १९वीं सदी में टेलीग्राफ के अविष्कार के साथ हो गया था। बाद में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, कम्प्यूटर, उपग्रह,टेलीविजन, इंटरनेट, मल्टीमीडिया इत्यादि ने प्रौद्योगिकी को वर्तमान क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्यकलापों में सूचना–संचार तकनीक के उपयोग को "ई–गर्वनेंस" नाम दिया गया है। चूंकि शासन के कार्यक्षेत्र व कार्यकलाप काफी व्यापक होते हैं इसलिए ई–प्रषासन का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। शासन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, नित नये–नये क्षेत्रों से सूचना तकनीक को जोड़ने का कार्य जारी है।

२१वीं सदी का युग इन्टरनेट का युग माना जाता है जिसके तहत ई–प्रषासन द्वारा प्रशासनिक कार्यकलापों को आम नागरिक के नजदीक कर दिया गया है। यह क्रांति प्रषासन के नीति निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करती है। जिससे प्रषासन के लिए ई–प्रशासन आवश्यक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। ई–प्रशासन की योजना में २७ परियोजनाएँ मिषन के रूप में तैयार की गई हैं। जिनमें से ०९ परियोजनाएँ केन्द्र सरकार के अधीन होगीं। जिनके तहत् आयकर, कम्पनी मामले, पासपोर्ट, पेंशान, केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क इत्यादि विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। जबकि कुछ परियाजनाएँ राज्य सरकारें संचालित कर रहीं हैं। जिनमें कृषि, भू–अभिलेख, पुलिस कोशालय, सम्पत्ति कर, वाणिज्य कर, सड़क परिवहन, नगर निकाय एवं पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों के क्रिया कलापों में ई–प्रशासन के एक न्यूनतम एजेण्डे की प्रगति को मॉनीटर किया जाता है। इस न्यूनतम एजेण्डा में अन्य बातों के साथ–साथ सरकार से सरकार तथा सरकार से नागरिक संचालन की अवसंरचना को बुनियादी तौर पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है, इस न्यूनतम एजेण्डा के लिए पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराना, लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) की व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, वेबसाईटों को तैयार करना, वेबसाईट पर कार्य उपलब्ध कराना, प्रपत्रों को भरकर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की व्यवस्था तथा नागरिक क्षेत्र में सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन जिसमें नियम तथा अधिनियम भी शामिल हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि ई–शासन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को उनकी जरूरत की मूलभूत सेवाएं एवं उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध करायी जाए ताकि उन्हें बार–बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ें तथा विचौलियों से भी उनकी रक्षा की जा सके। इसके एक साथ कई लाभ हैं, एक तो आम लोगों को शीघ्र सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी और उन्हें कोई गलत सूचना देकर बहका भी नही सकेगा। इन उद्देष्यों के निर्वहन में ई–प्रशासन की भूमिका एक सशक्त और बहुआयामी माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। शासन की विविध योजनाओं और नागरिकों के हितार्थ किए जाने वाले कार्यकलापों से आम जनता को सीधे रूबरू होकर लाभान्वित होने में "ई–प्रशासन" एक श्रेयस्कर सोपान है जिससे एक लोकतांत्रिक ढांचे की संरचना का सुदृढ़ होना निश्चित ही है।

प्रशासनिक विकास में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनियोजित संगठित होने के साथ–साथ निरंतरता एवं सृजनशीलता की भी अपेक्षा करती है। प्रशासन में नवाचार लाने का उद्देश्य जनता की आकांक्षाओं तथा इच्छा को पूरा करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदि सुधार किये जाते हैं। नवाचार का प्रशासनिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान सामने आ रहा है। जिसके द्वारा प्रषासन में इस प्रकार के सुनियोजित परिवर्तन लाना है जो कि अपनी क्षमताएं बढ़ा सके एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके।

प्रशासन में नवाचार लाने का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को सशवत, मित्तव्यापी, स्वच्छ, संवेदनशील, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना है। प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से कार्य करना जिससे नवाचार का विकास हो सके, इनके अंतर्गत लोगों के बृहद दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया है जिनसे उनमें नये सुझाव तथा विचार प्राप्त हो सके। प्रशासनिक कार्यों में केवल कार्य विधियों एवं उपयुक्त विधियों से कार्य करने पर ही अधिक बल नहीं दिया जाता बल्कि कार्यों में नया ढंग, कार्य करने का अलग–अलग रूप से परिवर्तन होना चाहिए, जिससे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और कुशलता भी प्राप्त की जा सके।

प्रशासन में नवाचारों से आशय प्रक्रियाओं समय–समय पर होने वाले परिवर्तनों से है, जिससें सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रम दोनों ही शामिल होते हैं। प्रशासन के विकास के लिए एक सुसंगठित संगठन बनाना, नवनिर्मित औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास, साधन, उपकरण, मशीनीकरण, का होना अत्यंत आवश्यक है इन सभी साधनों के होने से प्रषासन की कार्यप्रणाली में तीव्रता तथा गतिशीलता पाई जाती है। शासन द्वारा विभिन्न योजना संचालित की जाती हैं, जिससे संपूर्ण प्रषासन में प्रशासनिक विकास का योगदान होता है और प्रगतिशील पदाधिकारी प्रषासन, सुसंगठित विधियां एवं प्रक्रियाएं, सुदृढ़ कार्यालय प्रबंध, स्वचालान का प्रयोग, कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जाना प्रबंधकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि प्रशासनिक विकास का योगदान है। इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर प्रशासन में लचीलापन, जनौन्नमुख, पारदर्शिता आती है और शासन में जटिलता तथा भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। एक सुसंगठित प्रशासन के लिए इन सभी प्रक्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे देश का विकास तथा नागरिक में जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।

ई–प्रशासन का प्रशासनिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ई–प्रशासन की उस क्रांति से प्रशासन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। यह क्रांति प्रशासन के नीति–निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करती है जिससे प्रशासन के लिए ई–प्रशासन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। प्रशासन में ई–प्रषासन पद्धति को अपनाकर किसी भी एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह तथा संपूर्ण विश्व में सूचनाओं का आदान–प्रदान करके कहीं भी किसी भी समय आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ई–प्रशासन २१वीं शताब्दी का युग जाना जाता है, जिसतें इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक गांव में बदल गया है। अर्थात हम अपनी बात बड़ी ही आसानी से और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हैं और किसी भी सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। इस परियोजना को क्रियान्वित करने का उद्देश्य ''ग्रामीण जनता'' को लाभान्वित करने से है।

ई–प्रशासन परियोजना का माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर विभिन्न सरकारी बेबसाइट को हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विकास किया गया है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है जो इंटरनेट कम्प्यूटर तथा ई–मेल जैसे माध्यमों से नागरिक और प्रशासन को एक दूसरे के आमने–सामने लाकर खड़ा कर दिया हैं प्रशासन न केवल त्वरित, कुशल हो रहा है अपितु पारदर्शी भी बनता जा रहा है। नागरिकों को उनके कामकाज संबंधी सूचनाएं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी ऑनलाइन मिलने लगी है ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ता जिससे समय तथा व्यय की बचत होती है।

ई–प्रशासन परियोजना के माध्यम से सूचनाएं वास्तव में ग्रामीण जनता तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए देश की सभी पंचायतों में सिटीजन कियोस्क (ई–गुमटियां) स्थापित की गई है जिसमें निजी क्षेत्र व स्वयं सेवी संगठनों (NGO) की भी मदद ली जा रही है और सूचना सेवाओं को गांवों में केन्द्रित किया जा रहा है। ई–प्रषासन की योजना में २७ परियोजनाएं मिशन के रूप में तैयार की गई है इनमें से नौ (९) परियोजनाएं केन्द्र सरकार के अधीन होगी जिनके अंतर्गत आयकर, कंपनी मामले,

पासपोर्ट, पेंशन, केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बीमा इत्यादि विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जबकि राज्य सरकार की परियोजना के अंतर्गत कृषि, भू–अभिलेख, पुलिस, कोशालय, संपत्ति कर, वाणिज्यिक कर, सड़क परिवहन, रोजगार कार्यालय, नगर निकायों, पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण, ई–खरीद, ई–अदालतें इत्यादि इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इन सभी विभागों में ई–प्रशासन की पद्धति को अपनाकर प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है।

ई–प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना कैसी है कितनी है, कितनी अपडेट है और इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जा रहा है इन सबके लिए कार्यालयों के संपूर्ण संगठन में परिवर्तन की जरूरत होती है क्योंकि ई–प्रशासन से जुड़े हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की लागत सिर्फ १०–१५ प्रतिशत होती है शेष ८५ प्रतिशत भाग तो संगठन संबंधी प्रबंध होता है। इंटरनेट के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याएं संबंधित विभाग में या अधिकारी को भेज सकते हैं। ई–जुडिशियरी के जरिए न्यायिक कार्यों में हो रहा विलंब दूर होगा, शिक्षा के लिए ई–ऐजुकेशन, थानों में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु ई–एफ.आई.आर. आदि सुविधाएं शुरू की जा रही है।

ई–प्रशासन की पद्धति को अपनाकर प्रशासन में अत्यधिक लाभ हुए हैं जो इस प्रकार से हैं :–

(१)ई–प्रशासन सरकार और लोगों के बीच सहज संवाद का प्रतीक है। इंटरनेट, ई–मेल आदि के माध्यम से सरकार अपने नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने में सक्षम है।
(२)ई–प्रशासन से पुरानी दुष्क्रियात्मक प्रक्रिया से सरकार को छुटकारा मिल रहा है और कार्यप्रणाली में नवीनता लाई जा रही है।
(३)दूरदराज के गांवों को शहरों में स्थित सरकारी दफ्तरों से जोड़कर दूरी को कम किया जा रहा है।
(४)इसमें नागरिकों के समय तथा व्यय की बचत होती है।
(५)प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।
(६)प्रशासन में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और सही आंकड़े एवं सूचनाएं सदैव उपलब्ध रहेगी।
(७)ई–प्रशासन से नौकरशाही में कमी आएगी तथा लालफीताशाही को दूर किया जा सकेगा।
(८)कम्प्यूटरों के माध्यम से समन्वय आसान एवं उत्तर होने लगा है।
(९)भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सरकारी राजस्व वसूली पर्याप्त ढंग से हो सकेगा।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभागः–

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मंत्रालयों, विभागों के क्रियाकलापों में ई–गवर्नेंस के एक न्यूनतम ऐजेण्डे की प्रगति को मॉनीटर किया जाता है। इस न्यूनतम ऐजेण्डा में सरकार से सरकार तथा सरकार से नागरिक संचालन की संरचना को बुनियादी तौर पर सुनिश्चत करने की व्यवस्था की जाती है। इस न्यूनतक ऐजेण्डा में पीसी (पर्सनल कम्प्यूटरी) उपलब्ध कराना, एल.ए.एन. (लोकर एरिया नेटवर्क) की व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, बेबसाइटों को तैयार करना, बेबसाइट पर कार्य उपलब्ध कराना, प्रपत्रों को भरकर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था तथा सूचना का इलेक्ट्रानिक प्रकाशन जिसमें नियम तथा अधिनियम भी शामिल है। भारत सरकार से संबंधित विभाग मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध के रूप में नामित किया गया है।

इस विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण द्वारा पाया गया कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने अपनी–अपनी बेबसाइट तैयार कर ली है, वेतन लेखा प्रणाली को भी कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा लेकर एरिया नेटवर्क की व्यवस्था की जा चुकी है और ई–मेल, ऑनलाइन नोटिस बोर्ड, शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर के प्रयोग, बेबसाइट पर प्रपत्रों को उपलब्ध कराना, प्रपत्रों को भरकर ऑनलाइन पर प्रस्तुत करने की सुविधा तथा ऑनलाइन सेवा प्रदान करने का संबंध मंत्रालयों/विभागों कार्य किया जा रहा है।

ई–प्रषासन के माध्यम से आमजनों (सामान्य नागरिक) की शिकायतें और समस्याओं का तुरंत निराकरण करने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शासन की जनसुविधाओं का लाभदिया जा रहा है। ई–गवर्नेंस के अंतर्गत संचालित विभिनन गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी है और नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई सुविधाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। ''समाधान एक दिन में'' योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों को जोड़कर जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला डाटा केन्द्र स्थापित है, जहां जरूरतमंद को खसरा और बी–१ की कम्प्यूटरीकृत नकलें दी जाती है। भू–अभिलेख की मोबाइल यूनिट भी गांव–गांव पहुँचकर कम्प्यूटरीकृत नकलें ग्रामीणों को दी जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जिले में टेली मेडीसिन व्यवस्था प्रारंभ की गई है, इस व्यवस्था में जिला मुख्यालय से दूरस्थ स्थिति सामुदायिक केन्द्रों पर उपचार कराने वाले ग्रामीणजनों को विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध टेली मेडीसिन सुविधा को सामुदायिक केन्द्र से जोड़ा गया है, जहां उपलब्ध चिकित्सक जिला मुख्यालय पर उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श प्राप्त कर मरीजों को लाभान्वित किया जाता है।

ई–शासन ऑनलाइन सेवाः–

(1) ऑनलाइन परिवहन सेवा :–

- ट्रेन टिकट ऑनलाइन।
- ऑनलाइन द्वारा ट्रेनों को चलाने की स्थिति जांच करें।
- एयर इंडिया का टिकट ऑनलाइन प्राप्त करें।

Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

- यात्रा राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए।

(2) ऑनलाइन नागरिक सेवा :–

- पासपोर्ट के लिए लागू करे ऑनलाइन।
- पेन कार्ड के लिए आवेदन करे ऑनलाइन।
- सार्वजनिक उपयोगिता फार्म ऑनलाइन द्वारा।
- मतदाता सूची में अपना नाम खोजे ऑनलाइन।

(3) डाक एवं दूरसंचार सेवा :–

- ई–मेल के माध्यम से अपना संदेश भेजे पोस्ट।
- IMO (Internet Money Order) के माध्यम से अपने पैसे भेजे।
- ऑनलाइन द्वारा स्पीड पोस्ट की स्थिति को जानना।
- आई डी (ID) कोड की खोज करे ऑनलाइन।
- अपने शहर का पिन कोड खोज करे ऑनलाइन।
- गणना डाक शुल्क ऑनलाइन।

(4)व्यावसायिक सेवाएं :–

- ऑनलाइन द्वारा वाणिज्यिक कर भेज सकते है।
- ऑनलाइन द्वारा पंजीकरण (Gov)डोमेन के के लिए।
- ऑनलाइन द्वारा Gov निविदा के लिए आवेदन।

(5) ऑनलाइन मार्केट (बाजार) जानकारी :–

- ऑनलाइन द्वारा दैनिक कृषि वस्तुओं की दर।
- ऑनलाइन द्वारा अपने उत्पादों को ग्रामीण बाजारों में बेंचे।

(6)ग्रामीण विकास :–

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी प्राप्त करें ऑनलाइन द्वारा।
- अपनी ग्राम पंचायत खोजे ऑनलाइन द्वारा।
- खादी ग्रामोद्योग आयोग के पाठ्यक्रमों के लिए लागू करे ऑनलाइन।
- सरकारी योजनाओं के बारे में पता करें ऑनलाइन।
- जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करे ऑनलाइन।

(7)ऑनलाइन शैक्षिक सेवा :–

- डाऊनलोड करे NCRT पुस्तकें ऑनलाइन द्वारा।
- ऑनलाइन द्वारा परीक्षा परिणाम देखें।
- ऑनलाइन द्वारा रोजगार समाचार।
- ऑनलाइन द्वारा छात्रवृत्ति के लिए लागू करें।
- अपने अध्ययन के अध्ययन केन्द्र खोजें ऑनलाइन द्वारा।

(8)भारत की जानकारी :–

- भारत की यात्रा राष्ट्रीय पोर्टल ऑनलाइन।
- भारत के जिले के बारे में जानकारी प्राप्त करें ऑनलाइन द्वारा।
- भारत और राज्यों के मानचित्रों की जानकारी ऑनलाइन द्वारा।

(9)शिकायत निवारण :–

- किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत दाखिल कर सकते है ऑनलाइन द्वारा।
- अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते है ऑनलाइन द्वारा।

Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

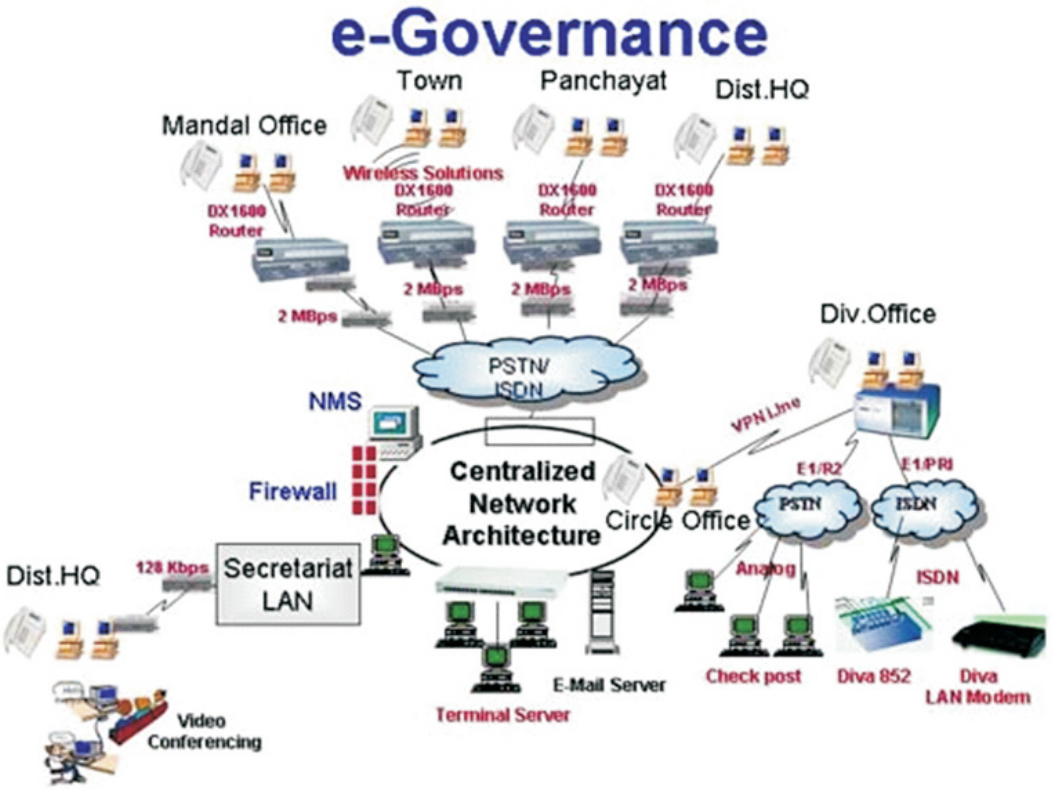

निष्कर्ष

ई–गवर्नेंस वर्तमान समय की एक नई अवधारणा के रूप में गुंजायमान हुई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरूचि के साथ ही प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। ई–प्रशासन जनआकांक्षाओं के राष्ट्रीय आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्षम विकास और प्रभावपूर्ण प्रशासन पद्धतियों के विकास के लिए आवश्यक है इसलिए प्रशासन में ई–प्रशासन का उपयोग अधिक से होना चाहिए।

ई–प्रशासन का यह विस्फोट लोक–प्रशासन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक बदलाव लाने जा रहा। ई–गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सेवाएं और लाभ ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। ई–गवर्नेंस ने कम्प्यूटर, इंटरनेट तथा ई–मेल जैसे माध्यमों से नागरिक और प्रशासन को एक दूसरे के आमने–सामने खड़ा कर दिया है। इससे प्रशासन न केवल त्वरित, कुशल होगा अपितु पारदर्शी भी बनता जा रहा है, नागरिकों को उसके कामकाज संबंधी सूचनाएं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी ऑन लाइन मिलने लगी हैं जिससे उसके समय तथा व्यय की बचत होती है।

ई–गवर्नेंस एक तरह सुशासन की ओर ले जाने वाला ठोस कदम है, जहां पारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार से भय होगा, पेपरलेस होने के कारण पर्यावरण की रक्षा होगी, जहां घर बैठकर अपनी समस्याओं और सरकार के बीच हम सामंजस्य बैठा सकते है। लोक प्रषासन में ई–गवर्नेंस अधिक से अधिक उपयोग से धीरे–धीरे नौकरशाहीं की संख्या एवं पद कम करना आसान हो सकेगा। वर्तमान समय में जो कार्य कर्मचारी करते है वह कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने लगेगा और संगठन आवश्यक कर्मियों तक ही सीमित हो सकेगा। कम्प्यूटर आधारित फाइलिंग व्यवस्था होने से फाइलें लालफीतों में बंधी देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कार्य आसानी से कम समय में तथा कम व्यय में पूर्ण हो जाएगा।

शासन के कार्यकलापों में सूचना–संचार तकनीक के उपयोग को ई–गवर्नेंश का नाम दिया गया है, शासन का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है, इसलिए ई–गवर्नेंस का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। वर्तमान समय में सूचना–तकनीक का उपयोग इतना व्यापक हो गया है कि शासन का कोई भी क्षेत्र इससे दूर नहीं है। नये–नये क्षेत्रों से सूचना तकनीक को जोड़ने का कार्य जारी है। सूचना संचार तकनीक के उपयोग ने शासन तंत्र को अधिक प्रभावी एवं जन सामान्य के लिए तुलनात्मक दृष्टि से और अधिक सुलभ बना दिया है।

ई–प्रशासन एक सापेक्षिक संकल्पना है, जिसमें प्रशासन की कार्यप्रणाली में नवाचार लाए गए हैं। नवाचार से अभिप्राय, किसी भी प्रचलित व्यवस्था में नवीन तथ्यों अथवा विधियों को लागू करना अर्थात कार्यप्रणाली में नवीनता लाने और परिवर्तनों से है।

संदर्भ सूची :–

१.शशि शुक्ला : ''ई–गर्वनेंस – आल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी''– २००३ (मध्यप्रदेश हिन्दी

अकादमी)
२.अनुराग जैन –''बेस्ट प्रैक्टिस सक्सेसफुल ई–गवर्नेंस इनिसियेटिप्स वाय द स्टेट ऑफ एम.पी.'' २००६डिपार्डमेन्ट ऑफ इनफॉरमेंशन टेक्नॉलॉजी
३.मिताली सक्सेना –''आई.सी.टी. इन. रूरल इण्डिया: ईःगर्वनेंस'' २००८ (ICFAI UNIVERSITY)
४.ए.प्रभाकर –''स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन –ईःगर्वनेंस''२००३ अजन्ता बुक्स इंटरनेशनल
५.राकेश चेतल –''ईःगर्वनेंस एण्ड इण्डियन सोसायटी :एन इम्पेक्ट स्टडी ऑन ईःगर्वनेंस'' २००६ कनिष्का पब्लिसर्स डिस्ट्रीव्यूटर्स
६.मुरली डी. तिवारी–''आई. टी. एण्ड ईःगर्वनेंस इन इण्डिया''२००२ प्रकाशन मेकमिलन
७.रोहित राज माथुर– ''द स्टेट आई. टी. एण्ड डेव्लपमेन्ट'' २००५ सेज पब्लिकेशन
८.पीयूश गुप्ता – ''कम्पेन्डियम ऑफ ईःगर्वनेंस इनिसियेटिप्स इन इण्डिया'' २००८ यूनिवर्सिटीज प्रेस
९.डॉ चन्द्रप्रकाश भाम्भरी –''सिद्वांत एवं व्यवहार''१९९६ जय प्रकाशनाथ एण्ड कंपनी

डॉ. श्रद्धा गर्ग
अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, सागर (म.प्र.)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org